19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में ईटी नाउ इंफ्रा फोकस समिट में आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक डॉ. पी आर जयशंकर

आईआईएफसीएल के एमडी डॉ. पी आर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में आईटीसी मौर्य में ईटी इंफ्रा फोकस शिखर सम्मेलन में एक पैनल चर्चा के दौरान भारत में बुनियादी ढांचे क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता के बारे में बात की।

उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने और बेहतर पारदर्शिता लाने की जरूरत है।

उन्होंने ऋणदाता समुदाय के लिए परियोजनाओं की बैंक योग्यता में सुधार के लिए रियायती प्राधिकरण, डेवलपर्स और ऋणदाताओं के बीच त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से रियायती समझौतों में ऋणदाताओं को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में बात की।

परियोजना पूर्ण होने के जोखिमों को कवर करने के लिए एक क्रेडिट वृद्धि तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बोलते हुए, उन्होंने एक बीमा उत्पाद –पूर्णता जोखिम बीमा परियोजना (पीसीआरआई) की वकालत की, जो समाप्ति भुगतान को रियायती प्राधिकरण से अलग कर देगा और इसे तीसरे पक्ष के बीमाकर्ताओं को स्थानांतरित कर देगा। उन्होंने कहा, इससे न केवल सरकारी खजाने पर इस तरह के भुगतान का बोझ कम होगा, बल्कि समय पर भुगतान और ऋण की बेहतर कीमत भी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में बुनियादी ढांचे को पीढ़ीगत प्रकृति के रूप में देखा जाना चाहिए और इसके वित्तीय मॉडलिंग को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले कुछ वर्षों में परियोजना का आकार बढ़ गया है, लेकिन बैंकों की निवल संपत्ति, इतनी वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पाई है। इसके लिए, उन्होंने क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कई संस्थानों की आवश्यकता पर जोर दिया।

अंत में, उन्होंने कहा कि नियामकों को परियोजनाओं की बेहतर वित्तीय व्यवहार्यता हासिल करने के लिए सहायक होना होगा और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उधार प्रथाओं के अनुरूप, उधारदाताओं की देयता प्रोफ़ाइल पर आधारित होना चाहिए।